लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 549

03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र और प्राकृतिक रंजक

549. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण के अनुकूल और जैव-आधारित वस्त्रों (जैविक वस्त्र) की तेजी से बढ़ती वैश्विक मांग और इस क्षेत्र में देश की निर्यात संभावना से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और पारंपरिक वस्त्र समूहों के माध्यम से घरेलू स्तर पर जैविक वस्त्र के उत्पादन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने कृत्रिम और खतरनाक रसायनों के स्थान पर वस्त्रों में प्राकृतिक रंगों और रंजक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना या नीतिगत उपाय आरंभ किया है; और

(घ) क्या सरकार ने कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के समन्वय से, किसानों और संधारणीय वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचाने हेतु प्राकृतिक रंजक में उपयोग किए जाने वाले पौधों की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु और इस संबंध में सुनिश्चित बाजार संपर्क के लिए कार्यक्रम आरंभ किए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): पर्यावरण अनुकूल और बायो-बेस्ड वस्त्रों की वैश्विक मांग बढ़ती जा रही है और निर्यात की अच्छी संभावना है। सरकार ऑर्गेनिक, नए ज़माने के, पर्यावरण अनुकूल फाइबर और वस्त्रों के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए अनेक कदम उठा रही है:

i. वस्त्र मंत्रालय आठ क्लस्टर और चार फैशन हाउस में 'भारत में अपैरल फैशन आपूर्ति श्रृंखला से खतरनाक रसायनों को खत्म करना' नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य नए ज़माने के, पर्यावरण अनुकूल और ऑर्गेनिक फाइबर की प्रोसेसिंग और उत्पादन को आसान बनाना है, साथ ही उपभोक्ता जागरूकता के द्वारा सस्टेनेबल वस्त्रों की मांग में वृद्धि करना है।

ii. मंत्रालय ने एक ईएसजी टास्क फोर्स भी बनाई है जो सस्टेनेबल उत्पादन, सर्टिफिकेशन, निर्यात आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। इस टास्क फोर्स ने सर्कुलर संवाद और क्लस्टर आदान-प्रदान प्रणाली जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा अनेक उद्योग केंद्रित कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए हैं, जो घरेलू विनिर्माण, गुणवत्ता प्रमाणन आदि पर फोकस करते हैं।

iii. सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआईसीआर), नॉर्थ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा) आदि जैसे संस्थानों के माध्यम से कई सहयोगी पहल भी की हैं, जो इस प्रकार हैं: ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं का विकास, बायो-फाइबर सहित अच्छी गुणवत्ता के कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाना, वाणिज्यिक खेती के लिए प्राकृतिक रंगीन कपास की बीज किस्मों को जारी करना, और ऑर्गेनिक-प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास का उत्पादन बढ़ाना आदि।

(ग) और (घ): गारमेंट में प्राकृतिक रंगों और डाई के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अनेक पहल कर रही है:

i. सरकार, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत, अपने दो घटकों, अर्थात् 'मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम' और 'आवश्यकता आधारित विशेष अवसंरचना परियोजनाओं' के द्वारा प्राकृतिक/सब्जी रंगों को बढ़ावा देने और डाई हाउस स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद दे रही है।

ii. सरकार ने अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत प्राकृतिक रंगों से जुड़ी 3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

iii. सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) पहल शुरू की है, जिसमें कोई कमी नहीं होगी और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। आईएचबी के तहत, वस्त्र समिति, जो वस्त्र मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है, प्राकृतिक रंगों से बने उत्पादों सहित अन्य उत्पादों को रजिस्टर करती है।

iv. भारत टेक्स 2025 में, ऑर्गेनिक फाइबर, जिसमें मिल्कवीड, कपास, आदि शामिल हैं, के साथ-साथ प्राकृतिक रंगों का प्रदर्शन किया गया ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

v. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए ताकि उत्पादन, प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन और विपणन के लिए सहायता सहित क्लस्टर-आधारित तरीकों से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल सके।

***